

पारदर्शिता के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस योजना के तहत आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि किसने कितने रुपए के बांड खरीदे और किस पार्टी को दिए।

चुनावी बांड के रूप में अलग-अलग स्रोतों से धन देने के मप्से पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतमयोग्य है और लोकतंत्र बचाने के लिहाज से इस उम्मीद की एक विजय के तौर पर देखा जा सकता है। यों चंदा लेने के नाम पर चल रही इस व्यवस्था पर तामाम सवाल उठे रहे और इस पर रोक लगाने की मांग भी हीली रही।

साथ ही सक्षम संविधानिकता के संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत सुप्रीम को जा रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर चुनावी बांड की व्यवस्था को असंवेदनिक बताते हुए रह दिया है। अदानत ने यह व्यवस्था दी है कि अन्तर्राजनीक बांड को अन्तर रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है और इसके सहरे राजनीतिक पार्टीयों को अधिक मदद से उठके बदले में कृष्ण और प्रब्रह्म करने की व्यवस्था को बढ़ावा दिल सकता है।

पांच न्यायाधीशों की पीठ में सर्वसम्मति से अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को अन्तर्राजनीकी मुद्दे कराए गए और आयोग इस जानकारी को इकत्तेस मार्फत तक वेबसाइट पर प्रकाशित करना।

दरअसल, एक विचित्र तर्क यह थी कि व्यापक न्यायालय के जरिए भ्रष्ट तरीके से जमा किए जाने वाले धन पर काबू पाया जा सकता है। जबकि इसमें जिस स्तर पर पारदर्शिता की अद्वेष्यों की जाती रही, वह अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक प्राप्तकर्ता तरीका रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ज्ञातादर पार्टियों को भी इसके कांगे गई रही थी कि चंदे के रूप में धन का गोपनीय तरीके से लेनदेन हो।

गैर-तरल बहुत है कि इस योजना के तहत आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि चुनावी बांड की व्यवस्था के जरिए भ्रष्ट तरीके से जमा किए जाने वाले धन पर काबू पाया जा सकता है। जबकि इसमें जिस स्तर पर पारदर्शिता की अद्वेष्यों की जाती रही, वह अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक प्राप्तकर्ता तरीका रहा है।

ये सवाल भी उठे कि चुनावी बांड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान कौन सी रही है, इतिहास इससे भ्रष्ट तरीकों से दासिल धन को बढ़ावा दिल सकता है। इसकी एक अलोचना यह है कि यह योजना बांड कारोबारे पर घराने को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद के लिए बनाई गई थी।

विडब्बना यह है कि भारतीय राजनीति में चुनावी पारदर्शिता की मांग तो अक्सर को जाती है, मगर इसके लिए जरूरी कारोंकों को सुनिश्चित करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखती है। हाँरनी की बात यह भी कि यह योजना बांड कारोबारे पर घराने को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद के लिए बनाई गई थी।

इस बात की अशका निराधार नहीं रही है कि बड़ी कारोबारे कपनियां किसी पार्टी को मदद के तौर पर धन देने के लिए किस तरह की अधोवित सुविधाओं की मांग कर सकती हैं और ऐसे में चुनावी बांड के जरिए धन मूल्यों का रक्कार करने का नियम किसके लिए सवालें ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसका प्राप्ति असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर फैलता है।

अब लोकसभा चुनाव के पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिहाज से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक महत्व का और याद रखने लायक कहा जा सकता है।

दूसरे तरफ योजना के तहत आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि किसने कितने रुपए के बांड खरीदे और किस पार्टी को दिए।

हाँरनीका सर्वोच्च न्यायालय के जरिए चंदा देने का बड़ा कदम है। कोई प्रगतिशील व्यवस्था किसी की स्वीकृति के समान से राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता की जांच की जाए और यह योग्य अन्य कर्मकान्ड नहीं कर पाएं।

वास्तव में यह प्रगतिशील व्यवस्था और समाज नियमण की दिशा का बड़ा कदम है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कॉम्पन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करना कायदे से ऐतिहासिक घटना मानी जानी चाहिए।

गोवा में समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि तथा प्रक्रिया अलग है।

संविधानीक संहिता के समान से राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता की योग्यता अभियान की बांड की व्यवस्था को आधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है और इसके सहरे राजनीतिक पार्टीयों को आधिकार और प्रब्रह्म करने के लिए चंदा देने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की जारी रही थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने जैसा की वात संविधान स्वीकृति करने की ज



For Buying & Selling

Properties | Residential & Commercial Sites |
 Villas | Apartments & Plots |
 Farmhouse | Agriculture Land

+91 98715 77057 | 99995 11233

Email: info@propre.in

Web: www.propre.in

Location: Jewer Airport and Greater Noida